देश में घटी एलपीजी की खपत

ईरान संकट के बीच बदली तस्वीर, पीएनजी की ओर बढ़ रहे लोग

> एलपीजी की मांग में कमी केवल आपूर्ति संबंधी दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गैस की ओर बढ़ते रुझान और ऊर्जा उपयोग के बदलते तौर-तरीकों का भी असर दिखाई दे रहा है . पश्चिम एशिया के तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता ने सरकार और ऊर्जा कंपनियों के सामने वैकल्पिक व्यवस्था मजबूत करने की चुनौती भी बढ़ा दी है . आने वाले महीनों में एलपीजी की उपलब्धता, कीमतों और पीएनजी कनेक्शन के विस्तार पर नजर रहेगी, क्योंकि इनका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की ईंधन जरूरतों पर पड़ सकता है .

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 04 सितंबर भारत में घरेलू और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पानी रईस की खपत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच देश में एलपीजी की खपत करीब 16 फीसदी घटकर 11.3 मिलियन टन रह गई.

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 13.4 मिलियन टन था. तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के डेटा के मुताबिक, एलपीजी की खपत में यह कमी ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध के कारण एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है. इसके साथ ही सरकार अब ज्यादा से ज्यादा घरों को पीएनजी पानी जरिए मिलने वाली प्राकृतिक गैस से जोड़ने पर जोर दे रही है. के

पिछले माह पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ी अगस्त में भी एलजी की खरीद हुई अगस्त 2025 में 29 मिलियन टन एलपी इस्तेमाल हुई थी, वहीं अगस्त 2006 में यह घटकर 2.4 मिलियन टन रह गई औरत की खब की खपत 6.4 फीसदी बढ़कर 18.9 मिलियन टन हो गई.की बढ़कर 40.5 मिलियन ट सही. अगस्त में पेट्रोल की खपत 7.9 फीसदी बढ़कर 3.8 मिलियन टन और 6.4 के मुताबिक बारिश के पैटर्न में बला के कारण कई इलाकों लिए जा रहा था देश में एलपीजी की खपत में आई तेज गिरावट ने ऊर्जा इस्तेमाल के बदलते रुझान की तस्वीर सामने रखी है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच भारत में घरेलू और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की खपत करीब 16 फीसदी घटकर 11.3 मिलियन टन रह गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 13.4 मिलियन टन थी.

इंसानों जैसी सोच वाला एआई, नए मॉडल ने मचाई हलचल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 सितंबर. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में नए मॉडल को लेकर हलचल तेज हो गई है. दावा है कि यह मॉडल केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंप्यूटर पर कई जटिल काम खुद पूरा कर सकेगा. वेबसाइट बनाना, कोड तैयार करना, खेल विकसित करना और साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों को संभालना इसकी प्रमुख क्षमताओं में शामिल बताए जा रहे हैं. नया मॉडल कंप्यूटर आधारित कामों को पुराने मॉडल की तुलना में अधिक तेजी से पूरा कर सकता है. एक उदाहरण में दावा किया गया जिस मकान की तलाश में इंसान को करीब छह घंटे लग सकते हैं, उसे इस मॉडल ने दस मिनट से भी कम समय में पूरा किया.

96 प्रतिशत कारोबार रुपया-रूबल में

- यूएस -चीन दंग भारत-रूस ने किया कमाल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली , 04 सितंबर रूस-भारत कारोबार को रुपया-रूबल से बढ़ावा मिला है और 96% लेन-देन में इन दोनों मुद्राओं में हो रहे हैं. रूस और भारत ने रुपया और रूबल का इस्तेमाल करके भुगतान का एक कारगर सिस्टम बनाया है, जिसके जरिए अब दोनों देशों के बीच 96% कारोबार का सेटलमेंट इन्हीं करेंसी में होता है.

2024 में रूस और भारत के बीच व्यापार रिकॉर्ड 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यह 2022 में यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से तीन गुना हो गया है. इसकी एक खास वजह है. दरअसल भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण सस्ते मिल रहे रूसी तेल का आयात बढ़ा दिया. 2025 में जब ये प्रतिबंध और कड़े किए गए तो दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट आई, लेकिन 2026 की पहली छमाही में इसमें फिर से तेजी आई.

रूसी कंपनियों को थी शिकायत- रूसी कंपनियों ने पहले द्विपक्षीय लेन-देन में रुपये (जो पूरी तरह से कन्वर्टिबल करेंसी नहीं है) के जमा होने और ट्रेड असंतुलन की शिकायत की थी, क्योंकि रूसी तेल के बढ़ते आयात के मुकाबले रूस को भारत का निर्यात कम था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी 22 रूसी बैंक और 17 भारतीय बैंक द्विपक्षीय व्यापार में सेवाएं दे रहे हैं.

ट्रांजेक्शन एक मिनट से भी कम समय में हो रहे पूरे

अनुसार रूस और भारत के बीच 90% ट्रांजेक्शन 10 मिनट के अंदर पूरे हो जाते हैं, जबकि 50% से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक मिनट से भी कम समय में पूरे हो जाते हैं . बीते सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों की तारीफ की . दोनों देशों के बीच 2030 तक 100 अरब डॉलर का ट्रेड पहुंच सकता है .

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जियो के 10 साल बेमिसाल

- 5 .09 करोड़ तक पहुंचा ग्राहक आधार
- 58 .4 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी

नवभारत कनेक्ट

रायपुर, 4 सितंबर दस साल पहले मोबाइल हाथ में था, लेकिन इंटरनेट की रफ्तार और पहुंच आज जैसी नहीं थी। महंगा डेटा और सीमित कनेक्टिविटी डिजिटल दुनिया की राह में बड़ी बाधा थे।

वर्ष 2016 में रिलायंस जियो के आगमन के बाद देश के दूरसंचार परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया। मोबाइल इंटरनेट सुविधा से आगे बढ़कर रोजमर्रा की जरूरत बन गया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इस डिजिटल बदलाव के प्रमुख हिस्सेदार बने। सितंबर 2016 में सेवा शुरू होने के समय मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जियो के महज 8.9 लाख ग्राहक थे। जुलाई 2026 तक यह संख्या बढ़कर करीब 5.09 करोड़हो गई। यानी करीब एक दशक में कंपनी का ग्राहक आधार 56.6 गुना बढ़ा। जुलाई 2026 तक मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्किल में कुल 8.71 करोड़ मोबाइल कनेक्शन** हैं। इनमें जियो की हिस्सेदारी 58.4 प्रतिशत पहुंच चुकी है। अगस्त 2018 में एयरटेल और अक्टूबर 2019 में वोडाफोन आइडिया को पीछे छोड़कर नंबर-1 बनने के बाद जियो ने यह स्थान लगातार बनाए रखा है।

भविष्य के लिए हाइड्रोजन व परिवहन क्षेत्र में नवाचार पर जोर

इंडियन ऑयल के सहयोग से पुणे में ऊर्जा नवाचार कार्यक्रम आयोजित, 30 गहन-तकनीकी स्टार्टअप का होगा चयन

नवभारत कनेक्ट

पुणे, 4 सितंबर इंडियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वेंचर सेंटर और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के साथ मिलकर भारत के प्रमुख ऊर्जा नवाचार त्वरक कार्यक्रम एमसीह प्लस इग्नाइट के पुणे आउटरीच कार्यक्रम की सह-मेजबानी की.

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के मुख्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम का विषय 'ऊर्जा नवाचारों को आगे बढ़ाना' रहा. इसमें देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों, गहन-तकनीकी स्टार्टअप संस्थापकों और वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पद्म विभूषण डॉ. आर.ए. माशेलकर ने इस पहल को समय की मांग और परिवर्तनकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनियां भारतीय नवोन्मेषकों को प्रयोगशालाएं, संसाधन, मार्गदर्शन, पूंजी और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए एक साथ आ रही हैं. उन्होंने संस्थापकों से संपूर्ण समाधान विकसित करने का आह्वान किया, ताकि भारत 'भारत में निर्माण' से आगे बढ़कर 'भारत में नवाचार' और अंतत: 'भारत में स्वामित्व' की दिशा में आगे बढ़ सके. इंडियनऑयल के अध्यक्ष ए.एस. साहनी ने कहा कि आने वाले वर्षों में वैश्विक ऊर्जा मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है और भारत की विकास दर दुनिया से आगे रह सकती है.

आईआईटी मद्रास करेगा कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम का संचालन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किया जा रहा है . इसके सहयोगी ऊष्मायन केंद्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, वेंचर सेंटर, सी-कैंप और आईआईएमए वेंचर्स शामिल हैं . वेंचर सेंटर के निदेशक डॉ . प्रेमनाथ वेणुगोपालन ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के लिए हाल में शुरू किए गए उत्कृष्टता केंद्र की जानकारी दी .

15 सितंबर से दुकानदारों का यूपीआई हो सकता है बंद

- पेमेंट कंपनियों ने आरबीआई से डेडलाइन बढ़ाने की अपील की
- लाखों दुकानदारों का अब तक पूरा नहीं हुआ वेरिफिकेशन

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 सितंबर देशभर के लाखों छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के सामने डिजिटल पेमेंट को लेकर संकट खड़ा हो सकता है. पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से मर्चेंट्स की री-केवाईसी पूरी करने की 15 सितंबर की तय समयसीमा बढ़ाने की मांग की है.

कंपनियों का कहना है कि बड़ी संख्या में दुकानदारों का वेरिफिकेशन अभी बाकी है और निर्धारित समय में पूरी प्रक्रिया खत्म करना मुश्किल है.

री-केवाईसी पूरी नहीं होने की स्थिति में संबंधित मर्चेंट अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे दुकानदारों के लिए यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना प्रभावित हो सकता है. इसका सीधा असर उन छोटे कारोबारियों पर पड़ने की आशंका है, जो रोजाना लेन-देन के लिए क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स जैसी डिजिटल भुगतान सुविधाओं पर निर्भर हैं. करीब 10 लाख छोटे ऑनलाइन कारोबारियों पर इसका असर पड़ सकता है.

मस्क की दौलत में 54 .2 अरब डॉलर का उछाल

स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयर चढ़े, 922 अरब डॉलर हुई संपत्ति

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 4 सितंबर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति में एक ही दिन में 54.2 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है. स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयरों में जोरदार तेजी के बाद मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 922 अरब डॉलर हो गई.

ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांक के मुताबिक अब मस्क खरबपति बनने की दौड़ में केवल 78 अरब डॉलर दूर हैं. शेयर बाजार में तेजी

के साथ उनकी संपत्ति में यह उछाल आया है.

स्पेसएक्स के शेयर में गुरुवार, 3 सितंबर को 6.42 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और इसका भाव 149.74 डॉलर तक पहुंच गया. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के शेयर में भी 5.42 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 376.36 डॉलर पर बंद हुआ. दोनों कंपनियों में मस्क की बड़ी हिस्सेदारी होने के कारण शेयरों की तेजी का सीधा असर उनकी कुल संपत्ति पर पड़ा.

इससे पहले स्पेसएक्स के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की संपत्ति में कमी आई थी. हालांकि, वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे. अब शेयरों में ताजा उछाल ने उन्हें फिर से खरबपति बनने के करीब पहुंचा दिया है.

वाई-वाई नूडल्स बनाने वाली कंपनी पर एफएसएसएआई की कार्रवाई

नवभारत न्यूज नेटवर्क

अजमेर, 4 सितंबर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सीजी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अजमेर स्थित रूपनगढ़ संयंत्र में निरीक्षण के बाद कार्रवाई की है.

एफएसएसएआई ने कंपनी को आवश्यक मंजूरी और सुरक्षा उपायों के बिना वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है. निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, लाइसेंस और

पैकेजिंग से जुड़े कई उल्लंघन सामने आने की बात प्राधिकरण ने कही है. एफएसएसएआई के अनुसार, संयंत्र में फर्श से एकत्र किए गए टूटे हुए नूडल्स को बिना उचित ताप उपचार के भुजिया उत्पादों में दोबारा इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई.

एयरटेल द टीचर ऐप के 3 लाख उपयोगकर्ता

नवभारत कनेक्ट

नई दिल्ली, 4 सितंबर शिक्षक दिवस से पहले भारती एयरटेल फाउंडेशन ने अपने आजीवन

चार राज्यों और 12 आकांक्षी जिलों में साझेदारी

25 वर्षों में 43 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच

नि:शुल्क डिजिटल मंच द टीचर ऐप के देशभर में करीब तीन लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की घोषणा की है। नवंबर 2024 में शुरू किए गए इस मंच का उद्देश्य

शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए सीखने की सामग्री, कक्षा-केंद्रित उपकरण और सहयोगी समुदाय एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। यह मंच राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षकों को बदलती शैक्षणिक जरूरतों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।

फाउंडेशन के अनुसार द टीचर ऐप अब 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षक-विकास को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की सरकारों के साथ राज्य स्तरीय सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए साझेदारी की गई है। मंच पर चार हजार घंटे से अधिक सीखने की सामग्री और 45 से ज्यादा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण उपकरण उपलब्ध हैं।

नीति आयोग के सहयोग से आकांक्षी जिलों में आधारभूत साक्षरता, डिजिटल तत्परता और कक्षा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

समाचार विशेष

महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे पर फिर बढ़ी हलचल

मुंबई, 4 सितंबर. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे के बीच एक बार फिर मराठा और ओबीसी समाज के बीच तनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मंगलवार को हुई ओबीसी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की महत्वपूर्ण बैठक से तीन मंत्रियों ने दूरी बनाई. मंत्री छगन भुजबल, गुलाबराव पाटिल और संजय राठौड़ बैठक में शामिल नहीं हुए.

बताया जा रहा है कि तीनों मंत्री ओबीसी महामंडल के लिए पर्याप्त और उचित निधि का प्रावधान नहीं किए जाने से नाराज हैं. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. हालांकि, बैठक में उनकी अनुपस्थिति के कारणों को लेकर संबंधित मंत्रियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

मराठा आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी समाज के बीच बढ़ते विवाद की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने ओबीसी मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है. समिति का उद्देश्य ओबीसी समाज से जुड़े आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना है.

भाजपा नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इस समिति के अध्यक्ष हैं. समिति में अलग-अलग विभागों के मंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है. ओबीसी मंत्रिमंडलीय उपसमिति में अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा छगन भुजबल, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, संजय राठौड़, गुलाबराव पाटिल, अतुल सावे और दत्तात्रय भरणे सदस्य हैं. समिति के माध्यम से ओबीसी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, योजनाओं और आर्थिक आवश्यकताओं पर सरकार के स्तर पर चर्चा की जानी है.

बढ़ी राजनीतिक संवेदनशीलता

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है . मराठा आरक्षण को लेकर लिए जाने वाले फैसलों का ओबीसी समाज की ओर से भी लगातार मूल्यांकन किया जाता रहा है . ऐसे में ओबीसी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक से तीन मंत्रियों की अनुपस्थिति ने सरकार के सामने ओबीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है . अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार निधि आवंटन से जुड़ी मांगों पर क्या कदम उठाती है और अगली बैठक में नाराज मंत्रियों की भागीदारी होती है या नहीं .

मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी ...

गडकरी का बदलेगा मंत्रालय! महाराष्ट्र से किसे मिलेगी जगह?

नई दिल्ली, 4 सितंबर. क्या देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? क्या देश के सबसे चर्चित मंत्रालयों के नेतृत्व में कोई ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? जी हां, इस समय मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द ही एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई पुराने मंत्रियों को छुट्टी दी जा सकती है

और नए व युवा चेहरों को देश की कमान संभालने का मौका मिल सकता है. इस संभावित बदलाव की सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विभाग बदला जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी कैबिनेट विस्तार में कई चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं. जहां शानदार परफॉर्मन्स देने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रमोशन मिल सकता है, वहीं नितिन गडकरी के पास मौजूद मौजूदा विभाग को बदलकर उन्हें कोई दूसरा मंत्रालय सौंपा जा सकता है.

2027 और 2029 का बड़ा चुनावी गणित

बीजेपी का यह कदम केवल एक सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची-समझी चुनावी रणनीति है . साल 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं . इसके ठीक बाद साल 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं . इसी चुनावी बिसात को मजबूत करने के लिए मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण रा'यों को नया और मजबूत प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है .

दीपेंद्र हुड्डा का मामला पीछे हो गया

नई दिल्ली, 4 सितंबर. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान को बड़ा मुद्दा बनाया था, जो उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सासंद सज्जन कुमार के निधन पर दिया था.

दीपेंद्र ने स'जन कुमार के निधन को अपूरणीय क्षति करार दिया था. इसके बाद भाजपा उनके ऊपर हमलावर थी और अकाली दल ने तो मोर्चा ही खोला था.

लेकिन अब वह मामला दब गया है क्योंकि दिल्ली के तीन भाजपा सांसद उनसे आगे बढ़ कर स'जन कुमार की शोक सभा में चले गए. दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सहरावत और योगेंद्र चंदोलिया तीनों सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए.

गौरतलब है स'जन कुमार दिल्ली के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सजा पा चुके हैं और अन्य मामलों में आरोपी हैं. तभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तीनों नेताओं को डांट लगाई. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तीनों को पता है कि दिल्ली में उनकी राजनीति के लिए जाट वोट का कितना महत्व है.

विशेष | **नई केंद्रीय कार्यसमिति के गठन के बाद भाजपा की चुनावी रणनीति में अब आएगा बड़ा बदलाव**

योगी के साथ स्मृति का डबल इंजन प्लान!

लखनऊ, 4 सितंबर. यूपी चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है. सपा और बीजेपी में आने वाले दिनों में यूपी में महासंग्राम शुरू होने वाला है. इसकी सुगबुगाहट बीते दिनों बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद देखने को मिली, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी.

लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से मिली अप्रत्याशित हार के बाद स्मृति ईरानी यूपी से दूर चली गई थीं, लेकिन महासचिव बनने के बाद यूपी के मैदान में दोबारा बढ़ी सक्रियता और उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्स यह साफइशारा कर रहे हैं कि बीजेपी 2027 के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है. सवाल उठ रहा है कि क्या स्मृति ईरानी का यूपी में एक्टिव होना बीजेपी के लिए फायदों का सौदा होगा या कोई नुकसान? क्या बीजेपी उनके जरिए उत्तर प्रदेश की विशाल महिला वोटर्स को सीधे अपने पाले में करने की तैयारी में है?

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश और खासकर अमेठी से अपना नाता नहीं तोड़ा है. उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्सए सार्वजनिक कार्यक्रमों की तस्वीरें और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं से संवाद इस बात के गवाह हैं. भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और रा'य स्तर के संगठनात्मक ढांचे में स्मृति ईरानी का नाम एक बार फिर से केंद्र में आ गया है, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है.

क्या 2027 में ट्रंप कार्ड बनेंगी स्मृति?- राष्ट्रीय राजनीति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, जेन-जी आंदोलन के बाद बदले हुए हालत में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी है.

फायदे और नुकसान

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यूपी चुनाव 2027 में एक स्टार महिला प्रचारक की कमी को स्मृति ईरानी पूरा कर देंगी. यूपी बीजेपी के पास राज्य स्तर पर कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है . स्मृति ईरानी इस खालीपन को बखूबी भर सकती हैं . दूसरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानों का आक्रामक जवाब देने में स्मृति हमेशा सबसे आगे रही हैं . 2027 में जब कांग्रेस और सपा साथ चुनाव लड़ने के मूड में हैंए तो स्मृति की मौजूदगी बीजेपी के लिए डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग रोल तय करेगी .